

//-- सुविवार --//

जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं- एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं।

आज

बेबाक

जिस देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। इतनी बड़ी चूक को मामूली घटना बताकर जिम्मेदारी से भागने की कोशिश जाएं। यहां तक कि इस गंभीर घटना को राजनीतिक ड्रामा बताया जाए उस देश के नागरिकों का भगवान ही मालिक है। जिस देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री हिंसा की भेंट चढ़कर शहीद हुए हो उस देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में संश्र लगना वाकई हैरत अंगेज है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर राजनीति होना और भी दुर्भाग्यजनक है। पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल करने वाली इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

सूर्योदय

उदय : 7.14 प्रातः

अस्त : 5:42 संध्या

जनसंख्या

विश्व : 7,918,657,780

भारत: 1,400,956,590

बाजार

संसेक्स : 59,744.65

निफ्टी: 17,812.70

गोल्ड : 46,750 प्रति 10 ग्राम

चांदी : 60,400 प्रति किग्रा

अण्डा दर: 5.06 प्रति नग

आज का दिवस

कालजयी फिल्मकार बिगल: रॉय की पुण्यतिथि: आठ जनवरी: का दिन हिंदी सिनेमा के कालजयी: फिल्मकार बिगल रॉय के निधन और ब्रिटेन के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जन्मदिन का साक्षी है। भारतीय: सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की जब बात की जाती है तो ‘दो बीघा जमीन’, ‘सुजाता’, ‘बटिनी’ और ‘परिणीता’ फिल्म का जिक्र जरूर आता है। इन फिल्मों के निर्देशक: बिगल रॉय थे, जिनकी बनाई: फिल्में आज भी दर्शकों की कसौटी: पर खरी उतरती हैं। कैसर की वजह: से 8 जनवरी 1966 में 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने एक जीता जगहाह फिल्मफेयर: पुरस्कार, दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और कान फिल्म महोत्सव के: अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मधुमती 1958: में 9 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित: अपने कैरियर का एक रिकार्ड दर्ज: किया।

15 से 18 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन की गति बरकरार

भोपाल। प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोर-किशोरियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा देने के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान जारी है। अब तक 19 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। अभियान के प्रथम दिन साढ़े 7 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाकर मध्यप्रदेश ने देश में रिकार्ड कायम किया।

गरमा-गरम



अंदर के पृष्ठों पर 7 3 | आंचलिक 4 | अभिव्यक्ति 5 | आंचलिक 7 | छत्तीसगढ़

RNI NO.MPHIN/2017/72749 भोपाल, शनिवार 08 जनवरी 2022, शुक्ल पक्ष षष्ठी, विक्रम संवत-2078 वर्ष-05 अंक-247 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए भोपाल, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, व रांची से एक साथ प्रकाशित

जम्मू-कश्मीर, पंजाब, मणिपुर...10 राज्यों में हिंदुओं को भी अल्पसंख्यकों वाला फायदा

- **राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान तय करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आखिरी मौका**
- **जरिस्टस संजय किशन कौल और जरिस्टस सुंदरेश की बेंच ने केंद्र को जवाब के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया**
- **अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में राज्यों की आबादी के हिसाब से वहां अल्पसंख्यक तय करने की मांग की है**

नई दिल्ली (ए.)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को उस जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का 'आखिरी मौका' दिया, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका के अनुसार 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वे अल्पसंख्यकों के लिए बनी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से और समय मांगने के बाद केंद्र को 4 सप्ताह

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब



के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने इसी तरह के मुद्दे पर अलग-अलग उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने का बेंच से अनुरोध किया।

शीर्ष अदालत ने पांच समुदायों - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी - को अल्पसंख्यक घोषित करने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ कई उच्च न्यायालयों से मामले स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को भी स्वीकृति दी और

मामले को मुख्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया।

याचिकाकर्ता-अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बेंच से सुनवाई की निश्चित तारीख की मांग की लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले को सात सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

बेंच ने कहा, 'माहौल देखिए। इसे थोड़ा स्थिर होने दीजिए। अगले हफ्ते हम सिर्फ अत्यावश्यक मामले ले रहे हैं। हम नहीं जानते अगले दो-तीन हफ्तों में की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ कई उच्च न्यायालयों से मामले स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को भी स्वीकृति दी और

नियम टूटा तो रद्द होगी रैली सस्पेंड होंगे अधिकारी, आयोग सख्त

चुनाव में कड़े नियम लागू करेगा आयोग

नई दिल्ली (ए.)। बीते साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान नियमों में ढिलाई के चलते आलोचना का शिकार होने वाला चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। चुनाव आयोग ने इस बार तैयारी की है कि यदि किसी रैली में कोरोना नियमों का उल्लंघन होता है तो उसे तत्काल रोक दिया जाए। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को लापरवाही के आरोपों में सस्पेंड किया जाएगा। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनावों को लेकर आयोग ने होम मिनिस्ट्री से कहा कि रैलियों में यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो फिर नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

इस बीच हेल्थ मिनिस्ट्री ने चुनाव आयोग को बताया है कि यूपी समेत सभी चुनावी राज्यों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। अब तक उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 31 केस ही मिले हैं, जबकि



उत्तराखंड में 8, गोवा में 5 और पंजाब में 2 केस ही पाए गए हैं। यूपी में पॉजिटिविटी रेट फ्लिहाल 0.24% ही है, जबकि उत्तराखंड में 1.01 फीसदी है। मणिपुर में भी 1 फीसदी के करीब ही है, जबकि पंजाब में आंकड़ा 2 फीसदी से ज्यादा है। यही नहीं यूपी, उत्तराखंड और गोवा में वैक्सीनेशन की गति भी सही है। इसके अलावा पंजाब और मणिपुर में टीकाकरण में तेजी लाने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है।

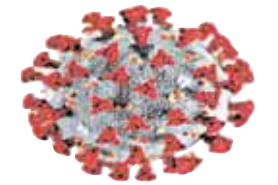
नियम टूटे तो तत्काल कैसिल हो जाएंगी रैलियां

चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि इस बार रैलियों में गाइडलाइंस कड़ी रहेंगी। नामांकन दाखिल करने, घर-घर प्रचार करने से लेकर बड़ी रैलियों तक में कोरोना के सख्त नियम लागू किए जाएंगे। यही नहीं मतगणना के दौरान भी नियम सख्त रहेंगे। सूत्रों ने कहा कि यदि रैलियों में नियम टूटते हैं तो फिर उन्हें कैसिल करने में कोई हिचक नहीं दिखाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में इस तरह की सख्ती कम ही देखने को मिली थी। इसके अलावा आयोग की ओर से पार्टियों को सलाह दी गई है कि वे ज्यादा से ज्यादा वचुअल तरीके से ही रैलियां करें। यही नहीं राजनीतिक दलों से चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग लेने का भी प्लान बनाया है कि नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

प्रदेश में कोरोना का कहर : ग्वालियर में फिर कोरोना विस्फोट, 111 नए मरीज मिले

भोपाल। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है।

शुक्रवार को 111 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यहां एक्टिव केस 435 हो गए हैं। मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1320 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं, शुक्रवार शाम सीहोर में कोरोना से 82 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। उसकी कोरोना रिपोर्ट दो दिन पहले पॉजिटिव आई थी। इसके अलावा, कोरोना को बंटे संक्रमण की वजह से पाबंदियां बंटे जा रही हैं। अब बिना मास्क पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। भोपाल में भोजपाल और विज्ञान मेला रद्द कर



दिया गया है। इंदौर में शुक्रवार को तीन फ्लाइंग निरस्त कर दी गई। फ्लाइंग निरस्त करने की वजह पैसेजर्स का न मिलना बताया गया है। जबलपुर में 92 नए मामले सामने आए हैं। सागर में 38 नए मरीज सामने आए हैं। होशंगाबाद में 4 और छिंदवाड़ा में 5 नए केस मिले हैं। भोपाल में प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल शेष पृष्ठ 7 पर

भोपाल में कोरोना का असर, भोजपाल मेला कैसिल

राजधानी भोपाल के करीब 50 प्रतिशत हिस्से में कोरोना की एंट्री हो गई है। मंत्रालय से लेकर एगुकेशन, हेल्थ और रिसर्च सेंटरों में संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं, पॉटा इलाकों में भी कोरोना फैल चुका है। जंबूरी मैदान में 7 जनवरी से शुरू होने वाले विज्ञान मेले पर भी कोरोना का असर पड़ा है। सुबह 11 बजे होने वाले इनोवेशन से पहले गर्वनर मंगामाई पटेल का आना कैसिल हो गया। कुछ घंटे बाद यह मेला रद्द कर दिया गया।

देश में बहुत अधिक सार्वजनिक छुट्टियां, उन्हें बढ़ाने के बजाय कम करने का समय : बॉम्बे हाईकोर्ट

मुंबई (ए.)। देश में बहुत अधिक सार्वजनिक छुट्टी हैं और उन्हें बढ़ाने के बजाय कम करने का समय आ गया है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी दादरा और नगर हवेली में 2 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी में शामिल न किए जाने वाली याचिका को खारिज करते हुए की। दादरा नगर हवेली के एक निवासी ने सार्वजनिक छुट्टी न दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस दिन केंद्र शासित प्रदेश में छुट्टी हुआ करती थी क्योंकि इस दिन हमें पुर्तगाली शासन से मुक्त मिली



थी, इसे 2020 तक मनाया जा रहा था लेकिन 2021 से बंद कर दिया गया है।

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि सार्वजनिक छुट्टी के लिए कोई

कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार नहीं है और किसी विशेष दिन को सार्वजनिक छुट्टी या वैकल्पिक अवकाश घोषित करना सरकार की नीति का मामला है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल कोर्ट ने सुनवाई होगी और उसके बाद जो भी फैसला आया उसके हिसाब से आगे के दाखिलों में परिवर्तन लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों के तहत आरक्षण को चुनौती दी गई थी। इस चुनौती की वजह से कार्डसलिंग की प्रक्रिया रुक गई थी जिसके विरोध में देश भर में हजारों रैजिडेंट डॉक्टर पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे थे। हाल ही में ये डॉक्टर हड़ताल शेष पृष्ठ 7 पर

हालांकि उस पर अलग से मार्च में सुनवाई होगी और उसके बाद जो भी फैसला आया उसके हिसाब से आगे के दाखिलों में परिवर्तन लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों के तहत आरक्षण को चुनौती दी गई थी। इस चुनौती की वजह से कार्डसलिंग की प्रक्रिया रुक गई थी जिसके विरोध में देश भर में हजारों रैजिडेंट डॉक्टर पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे थे। हाल ही में ये डॉक्टर हड़ताल शेष पृष्ठ 7 पर

हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यदि देश के स्वतंत्रता दिवस को चिह्नित करने के लिए 15 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, तो ऐसा कोई कारण नहीं शेष पृष्ठ 7 पर

बुली बाई केस: मुख्य साजिशकर्ता नीरज ने उगले राज, 7 दिन की पुलिस रिमांड

नई दिल्ली (ए.)। बुली बाई ऐप केस में मुख्य साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई दिल्ली पुलिस के कब्जे में हैं। पुलिस की इंटरगेशन में उसने कई राज खोले हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसने ऐप बनाने और ट्विटर अकाउंट्स को लेकर कई बातों का खुलासा किया। कोर्ट ने बुली बाई केस में गिरफ्तार नीरज को सात दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ के मुताबिक, पुलिस के सामने पुष्टाव के दौरान बुली बाई ऐप केस के मुख्य साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई ने कहा, उसने ऐप को नवंबर 2021 में विकसित किया था।

यदि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है तो गृहमंत्री शाह इस्तीफा दे : मरकाम

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का रुकना यदि वे सुरक्षा चूक में आता है तो इसके लिये मुख्य रूप से जवाबदेह केंद्रीय गृह मंत्रालय है। गृहमंत्री अमित शाह इस चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दें। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं बल्कि एसपीजी की होती और एसपीजी सुरक्षा प्राप्त हर व्यक्ति का रूट चार्ट एसपीजी के निगरानी में होता है और वो 48 घंटे पूर्व में उन सारे जगहों को अपने अधीन कर लेते

हैं, पूरे रास्ते में एसपीजी के लोग अपने हिसाब से सुरक्षा घेरा बनवाते हैं, राज्य प्रशासन भी उन्हीं के मातहत होता है। क्या एसपीजी ने ऐसा नहीं किया ? और यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया और नहीं करने के कारण एसपीजी के प्रमुख और गृहमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे इस्तीफा कब लिया जाएगा? भिोजपुर में जहां किसानों ने रास्ता रोका वह क्षेत्र राज्य सरकार के पुलिस के अंतर्गत आता ही नहीं क्योंकि मोदी सरकार के =दखलदानी नीति= के कारण हाल ही में बॉर्डर क्षेत्र के 50 किमी क्षेत्र को बीएसएफके निगरानी में दे

दिया गया है और वो रास्ता बॉर्डर के 10 किमी दूरी पर है तो क्या केंद्र सरकार मानती है कि बीएसएफ ने पीएम के सुरक्षा क्षेत्र की निगरानी सही से नहीं की ? और यदि ऐसा है तो बीएसएफके मुखिया होने के नाते गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री को हैलीकॉप्टर से 112 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी जैसा कि उनके कार्यालय से 04 जनवरी को जारी हुए दौरा कार्यक्रम में वर्णित है और उसी आधार पर सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी, आईबी, इंटेलिजेंस तथा केंद्रीय गृह विभाग द्वारा की गई थी पंजाब शासन के

साथ समन्वय करके, मगर उन्होंने अचानक से कार में जाने का फैसला आखिर किसके सलाह पर लिया और क्या 112 किमी सड़क को बिना पूर्व सूचना के सुरक्षाकर्मियों द्वारा घेर पाना सम्भव है? क्या अंतिम समय में इस बदलाव के जिम्मेदारों पर कार्यवाही होगी? यह तय है कि यह बदलाव राज्य प्रशासन ने नहीं बल्कि केंद्रीय प्रशासन या फिर स्वयं प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत स्तर पर लिया है। केंद्र सरकार भी जानती है कि पंजाब में किसान मोदी सरकार के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सुपोषण अभियान के कारण छत्तीसगढ़ हो रहा है कुपोषण मुक्त

डू कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि

रायपुर/नवप्रदेश। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों में कुपोषण की दर 6.4 प्रतिशत कम होने पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को बधाई दी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में 6.4 प्रतिशत की कमी आई है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। कांग्रेस सरकार के कुपोषण मुक्ति

अभियान में अपार सफलता प्राप्त हो रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार ने 15 साल के शासन में कुपोषित बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होते।

प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा था कि राज्य में नक्सल से बड़ी समस्या 37.7 प्रतिशत बच्चों के कुपोषित होना है। अगर हम छत्तीसगढ़ के विकास के परिकल्पना करते हैं और हमारे राज्य का आने वाला भविष्य 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषित रहे

तो हमारी विकास की अवधारणा अधूरी है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2019 को कुपोषण मुक्ति महा अभियान

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की, जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं। छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 में हुए वजन त्यौहार में लगभग 4 लाख 33 हजार 541 कुपोषित बच्चों का चिन्हंकन किया गया था। इनमें से नवम्बर 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई

36.86 प्रतिशत अर्थात एक लाख 59 हजार 845 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद से लगभग 4 लाख 39 हजार बच्चों और 2 लाख 59 हजार महिलाओं को गरम भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर महिलाओं और बच्चों को पन्त, सब्जियों सहित सोया और मूंगफली की चिकी, पौष्टिक लड्डू, अंडा सहित मिलेट्स के बिस्कुट और स्वादिष्ट पौष्टिक आहार दिया गया। इससे बच्चों में खाने के प्रति

न्यूज गैलरी

डॉ. डहरिया ने मंदिर हसौद चंदखुरी मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का किया शुभारंभ



रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विभाग तथा श्रम मंत्री डॉ. डहरिया ने मंदिर हसौद चंदखुरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। सड़क कार्य की लागत 36 करोड़ 24 लाख रूपए है तथा यह सड़क का कार्य 10.40 किलोमीटर की लम्बाई का है। इस मार्ग के बन जाने से वाहनों के आवाजाही में खे रही दिक्कत नहीं होगी। शुभारंभ अवसर पर डॉ. डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सड़क पुल पुलिया सहित जनसुविधा के सभी जरूरी कार्य कराये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में विदेश ठाकुर, कोमल साहू, रामचंद्र वर्मा, शारदा देवी वर्मा, खिलेश देवागन, सौरभ चंद्राकर, मयंक तिवारी, प्रफुल्ल वर्मा, प्रेमलाल ढीबी सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

कुर्क शुदा संपत्ति की हुई नीलामी

रायपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर तहसील कार्यालय रायपुर के सभागृह में सत्र न्यायाधीश रायपुर के विधिक दायित्व प्रकरण में पड़ित आदेश एवं जिला दण्डाधिकारी तथा एसडीएम रायपुर के जारी आदेशानुसार निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत अनावदेकगण के कुर्क शुदा संपत्ति की नीलामी कार्यवाही की गई। जिसमें इच्छुक प्रतिभागी द्वारा अंतिम बोली लगाकर ऋय किया गया है। जिसमें सन एंड सन इन्फ्रामैट्रिक प्रा. लि. के रथामसुन्दर शर्मा पिता बिजमोहन शर्मा निवासी मालवीय रोड रायपुर द्वारा गाम अमलीडीह स्थित संपत्ति/भूमि खसरा नंबर 191/21 कबला 0.324हे. भूमि का सरकारी ऑफसेट मूल्य 9 लाख 39 हजार रूपये था जिसे नीलामी पश्चात 3 करोड़ 84 लाख में बोली लगाकर ऋय किया गया। इसी प्रकार विनोद अगवाल निवासी राठी जंगीगढ़ चापा द्वारा खसरा नंबर 190/14 रकबा 0.011हे. सरकारी ऑफसेट मूल्य 9 लाख 62 हजार 500 रूपये था। जिसकी नीलामी पश्चात 9 लाख 63 हजार 500 रूपये में ऋय किया गया तथा खसरा नंबर 190/06 रकबा 0.022 हे. भूमि का ऑफसेट मूल्य 1 लाख 92 हजार 500 रूपये था। जिसका नीलामी पश्चात मूल्य 21 लाख 29 हजार रूपये की बोली लगाकर ऋय किया गया।

दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना गाइड लाइन का पालन अनिवार्य

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर सौरभ कुमार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी व्यवसायिक संस्थानों तथा व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तथा अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कराएं । अपने आदेश में उन्होंने यह भी उल्लेखित किया है कि सभी व्यवसायी को अपने दुकान एवं संस्थान में विराम हेतु मास्क एवं सैनेटाइजर रखें, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय और वितरण किया जाए तत्पश्चात अन्य वस्तुओं का विक्रय किया जाए। इसी तरह व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारियों एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कोविड–19 से संबंधित जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

रायपुर/नवप्रदेश।कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश पर कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिले में लोगों की सुविधा के लिए 24×7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिन लोगों को कोरोना की जांच, आइसोलेशन की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, पुंखुलेख, डॉक्टर से परामर्श या अन्य चिकित्सा संबंधी जानकारी लेनी है, वे नियंत्रण कक्ष के इस टोल फ्री नं.- 78801-00331, 77124-45785, 78801-00332 में संपर्क कर सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र में 3 शिफ्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की इट्यूटी लगाई गई है ।

कोरोना की रोकथाम एवं नियंत्रण के हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

रायपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर सौरभ कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्यकार्यालालन अधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने कोरोना वायरस तथा इसके निवर्तन हेतिएंट ओमिगॉन के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिले के ग्रामीण अंचलों में आवश्यक कार्यवाही एवं समन्वय हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके तहत एकैके जोगी, परियोजना अधिकारी, को माइक्रो कनेक्शन जोन बनाने हेतु, विदेश से आने वालों की टैस्टिंग एवं होम आइसोलेशन हेतु कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क आने वाले व्यक्तियों की टैस्टिंग एवं आवश्यक समन्वय हेतु, कोविड जाँच एवं रिपोर्टिंग हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए मुख्य कार्यालालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को जनपद स्तर नोडल अधिकारी बनाया गया है। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों की टैस्टिंग एवं आवश्यक समन्वय हेतु डॉ. एस.जोसेफ, परियोजना अर्थशास्त्री, जिला पंचायत को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तथा मुख्य कार्यालालन अधिकारी, जनपद पंचायतों को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी बनाया गया है।

प्रदेश में तेजी से हो रहा है 15 से 18 वर्ष के किशोरों का टीकाकरण

डू मुंगेली, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद में शुरूआती 4 दिनों में ही कुल लक्ष्य के आधे से ज्यादा किशोरों का टीकाकरण

रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। विगत 3 जनवरी को इस आयु वर्ग के टीकाकरण की शुरुआत के बाद पहले चार दिनों में ही कुल लक्ष्य के 38 प्रतिशत किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। मुंगेली, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद जिले में शुरूआती चार दिनों में ही कुल लक्ष्य के आधे से ज्यादा किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं बालोद, बेमेतरा, कांकेर, गरियाबंद और कोंडागांव भी इसके करीब



है। प्रदेश में कुल 16 लाख 39 हजार 811 किशोरों के टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक (6 जनवरी तक) छह लाख 18 हजार 089 को कोरोना वैक्सिन का पहला टीका लगाया जा चुका है। कुल 16.4 लाख किशोरों के टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध पहले 4 दिनों में 6.18 लाख से अधिक को

लगाया गया टीका सभी जिलों में बनाए गए टीकाकरण सइट्स में किशोर-किशोरी उत्साह से पहुंचकर टीका लगावा रहे हैं। वर्ष 2005, 2006 और 2007 में पैदा हुए किशोरों का इन केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच मुंगेली जिले में 67

प्रतिशत, राजनांदगांव में 57 प्रतिशत, धमतरी में 56 प्रतिशत और महासमुंद में 51 प्रतिशत किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं बालोद और बेमेतरा में 15 से 18 वर्ष के 48-48 प्रतिशत, कांकेर में 47 प्रतिशत, गरियाबंद में 46 प्रतिशत, कोंडागांव में 45 प्रतिशत और बलौदाबाजार-

भाटापारा में 40 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। मुंगेली में 32 हजार 737, राजनांदगांव में 54 हजार 980, धमतरी में 27 हजार 180, महासमुंद में 32 हजार 993, बालोद में 23 हजार 625, बेमेतरा में 26 हजार 672, कांकेर में 21 हजार 471, गरियाबंद में 17 हजार 162, कोंडागांव

में 16 हजार 327, बलौदाबाजार-भाटापारा में 37 हजार 526, दुर्ग में 41 हजार 064, बिलासपुर में 40 हजार 200, रतेवाड़ा में 6242 और रायगढ़ में 29 हजार 686 किशोरों को टीका लगाया गया है। रायपुर जिले में 46 हजार 272 किशोरों को, जांजगीर-चोंपा में 32 हजार 836 को, जशपुर में 16 हजार 099, सूरजपुर में 15 हजार 041, कबीरधाम में 17 हजार 054, कोरिया में 11 हजार 737, बलरामपुर-रामानुजगंज में 13 हजार 563, सरगुजा में 14 हजार 988, गैरला-पेंड्र-मरवाही में 5838, बस्तर में 13 हजार, कोरबा में 18 हजार 074, बीजापुर में 2603, सुकमा में 2233 तथा नारायणपुर में 886 किशोर-किशोरियों को टीकाकरण की शुरुआत के पहले चार दिनों में दी गई है।

192 स्कूलों में किशोरों का शत-प्रतिशत हुआ टीकाकरण

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर जिले विकासखंड के 33 स्कूल, के 192 स्कूलों में 15 से 18 धरसीवां विकासखंड के आयु वर्ग के पात्र बच्चों 13 स्कूल ,नगर के प्रथम डोज का निगम बिरगांव के टीकाकरण कार्य शत 5 स्कूल तथा प्रतिशत हो चुका है। नगर पालिक गठ 3 जनवरी को इस महअभियान की 141 स्कूल शामिल शुरुआत की गई थी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर इन किशोर बच्चों की होसला अफमाई की थी। स्कूल के बच्चों ने भी टीकाकरण के प्रति भारी उत्साह दिखाया था और लाइन में लगर नि अपना टीका करवाया था। रायपुर जिले के जिन स्कूलों में टीकाकरण कार्य शत-प्रतिशत संपन्न हुआ है उसमें आरंग

कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन ने बुलाई एनजीओ की बैठक

डू कोरोना काल में नि:स्वार्थ सेवा के लिए एनजीओ हुए सम्मानित

रायपुर/नवप्रदेश। जिला प्रशासन द्वारा आज नागर की स्वयंसेवी एवं समाजसेवी संस्थाओं के प्रमुखों को आमंत्रित करके कोरोना की संभावित लहर को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही प्रशासनिक तैयारियों एवं एन.जी.ओ. की भूमिका के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में सांसद सुनील सोनी, महापौर एजाज ढेबर, जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा, अभनपुर विधायक धनेंद्र साहू, कलेक्टर सौरभ कुमार, जिला पंचायत सीईओ मयंक चतुर्वेदी, पार्षद आकाश तिवारी सहित शहर के एनजीओ सम्मिलित हुए। इस दौरान रायपुर की सभी संस्थाओं की सेवाभावना व निरंतर सहयोग के लिए सभी ने सराहना की एवं उपस्थित संस्था प्रमुखों को प्रशस्ति पत्र भी भेंट कर उनकी सेवाभावना को सम्मानित किया गया।

स्थानीय शहीद स्मारक भवन में आयोजित इस बैठक में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि

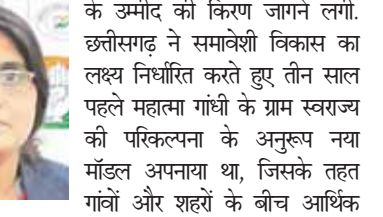


कोरोना की विषम परिस्थितियों से अपने शहर के लोगों को सुरक्षित करने सभी एनजीओ ने सतत 2 वर्षों से सेवाभाविता की जो मिसाल प्रस्तुत की है, उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। महापौर ढेबर ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की विभीषिका से निपटने जिस तरह रायपुर में एकजुट कार्य किए गए, उसकी वजह से रायपुर को पूरे देश में एक मॉडल शहर के रूप में देखा जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि पूरे जिले में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रशासन के साथ मिलकर

कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के लोगों को मिल रहा रोजगार : राजपूत

रायपुर/नवप्रदेश। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी संगठन द्वारा हाल ही में जारी किये गये बेरोजगारी के आंकड़ों ने एक बार फिर विश्वास के छत्तीसगढ़ मॉडल की रफ लता का परचम बुलंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2.1 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में चौथे नंबर पर आया है ये बड़े ही हर्ष और गर्व की बात है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता निर्णय के कारण प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार डॉ रमन सिंह सरकार में युवाओं के सपना टुटता गया और कांग्रेस सरकार में युवाओं के सपना सच होता गया और जब प्रदेश का जब मुखिया भूपेश बघेल है तो रोजगार



परस्परता बढ़ने पर जोर दिया गया है। इसी मॉडल के अंतर्गत गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुरजी गांव योजना, नखा-गरवा-धुवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडिशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रथम पृष्ठ का शेष....		
जम्मू-कश्मीर, पंजाब, ...	अनुरूप अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं।'	अस्पतालों का काम बाधित हुआ था. अदालत के फैसले का अधिकांश रेंजिडेंट डॉक्टरों ने स्वागत किया है. इस फैसले से करीब 50 हजारों डॉक्टरों के पीजी में दाखिले का रास्ता खुल गया है.
अधिनियम 2004 की धारा 2(एफ) की वैधता को भी चुनौती दी है और कहा कि यह केंद्र को बेलागम शक्ति देने है और स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन और अपमानजनक है।	प्रधानमंत्री मोदी का...	देश में बहुत अधिक ..
अधिवक्ता अधिनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 'वास्तविक' अल्पसंख्यकों को लाभ से वंचित करना और उनके लिए योजनाओं के तहत मनमाने और अनुचित संवितरण का मतलब संविधान के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।	शामिल होने के लिए बठिंडा से फिरोजपुर के लिए हेलिकॉप्टर के जरिए जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सड़क के रास्ते निकलना पड़ा था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी और अन्य सहयोगी पार्टियों ने इस चूक के लिए पंजाब में कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी किसी भी प्रकार के सुरक्षा में चूक से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि फिरोजपुर रैली में भीड़ कम होने के कारण पीएम मोदी ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। चन्नी ने इसे राज्य को बदनाम करने की साजिश करार दी है।	है कि 2 अगस्त को दादरा और नगर हवेली के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं किया जाना चाहिए। अधिवक्ताओं ने केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ के 15 अप्रैल 2019 के आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें 'गुड प्रहंडे' को प्रतिबंधित (वैकल्पिक) छुट्टी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन राजपत्रित छुट्टी नहीं। हाई कोर्ट में सवाल किया गया कि सरकार को गुड प्रहंडे को राजपत्रित अवकाश घोषित करने का निर्देश दिया था क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की आबादी में ईसाई शामिल थे। हालांकि तब सरकार ने तर्क दिया था कि चूँकि क्रिसमस और इसी तरह की छुट्टियों को व्यापक रूप से मनाया जाता है, इसने गुड प्रहंडे की
याचिका में कहा गया, 'प्रत्यक्ष और घोषित करें कि यहूदी, बहावाद और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो लदाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अल्पसंख्यक हैं, टीएएफ पाई रुलिंग की भावना के	नीट-पीजी दाखिलों ...	संस्कार है।
	पर भी चले गए थे जिसकी वजह से कई	संस्कार है।

छुट्टी को वैकल्पिक रखा। अधिवक्ताओं की ओर से सवाल किया गया कि सरकार 15 अगस्त और 26 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मना सकती है, लेकिन क्या वह दादर नागर हवेली के लोगों को 2 अगस्त का दिन (उनका मुक्ति / स्वतंत्रता दिवस) मनाने से रोकेंगी?

प्रदेश में कोरोना का कहर :

में इलाज के लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने पैकेज तय कर दिया है। बेड का चार्ज 5 से 17 हजार रुपए प्रतिदिन होगा। भोपाल के 5 प्राइवेट हॉस्पिटल में यही राशि चुकाना होगा। इनमें सिटी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, 24×7 ह्रद्वध मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और ग्रीन सिटी हॉस्पिटल शामिल हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिना मास्क वालों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके आदेश जारी किए जा रहे हैं।

